THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878
Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 05 Oct , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : आंतरिक सुरक्षा**	छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 28 नक्सलियों को मार गिराया
Page 01 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	जयशंकर SCO बैठक के लिए पाकिस्तान जाएंगे
Page 04 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	जयशंकर ने दिसानायके से मुलाकात की, आर्थिक सुधार के लिए भारत के समर्थन का वादा किया
Page 09 **Syllabus : GS 1 : भारतीय समाज**	समय से बाहर एक जनजाति
रिपोर्ट इन न्यूज़	एनविस्टेट्स इंडिया 2024
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 3 : आपदा प्रबंधन**	केरल को जोखिम वाले क्षेत्रों की तत्काल पहचान करने की आवश्यकता है

Page 01 : GS 3 : Internal Security : Challenges to Internal Security of India

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कम से कम 28 नक्सलियों को मार गिराया।

28 Naxalites killed by security forces in Chhattisgarh gunfight

This is the second-highest tally of Naxal casualties in any operation in the State; the number of insurgents killed this year touches 185; one policeman injured in grenade blast in Bastar region; anti-Naxal operations surged since BJP came to power

Shubhomoy Sikdar
RAIPUR

At least 28 Naxalites were killed by security forces in a gunfight in Chhattisgarh's Bastar region on Friday, according to the police.

One policeman was injured in a grenade blast during the operation.

The gunfight began around 1 p.m. in the Abujhmad area of Narayanpur district in the left-wing extremism-affected Bastar region. At 8 p.m., the police provided the final number of bodies recovered, after which Chief Minister Vishnu Deo Sai congratulated the forces in a post on X.

"In a fierce encounter between security forces and Naxalites in the border area of Narayanpur and Dantewada districts, reports suggest that 28 Naxalites have been killed. This major achievement by our brave soldiers is commendable. I salute their courage and indomitable spirit," Mr. Sai said.

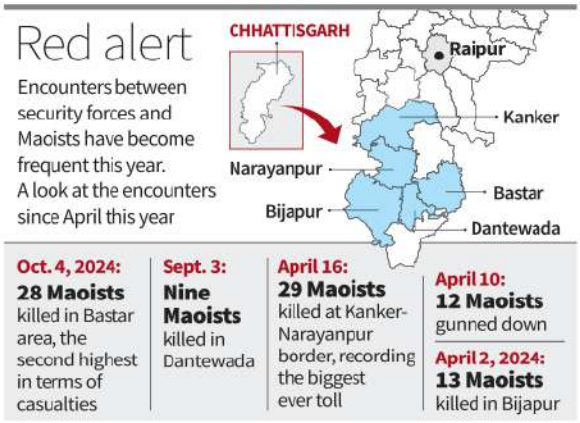

Arms found

In a statement issued earlier in the day, the police said a joint team of security forces from Dantewada and Narayanpur set out on an operation after receiving specific information about the presence of Naxalites in Abujhmad, a largely unsurveyed area in southern Bastar. The clash broke out around 1 p.m., after which firing continued at regular intervals. An AK47 rifle, a Self Loading Rifle (SLR) and other weapons were found at the site of encounter, the police said.

After Friday's anti-Naxal operation – the second biggest in terms of casualties inflicted by the State this year and in the conflict zone's history – the number of Naxals killed by the forces this year has shot up to 185.

There has been a surge in anti-Naxal operations since the new BJP government came to power in December 2023. Mr. Sai's post on X added: "Our fight to eliminate Naxalism will only end when we achieve complete success, and for this, our double-engine government is fully committed. The eradication of Naxalism from the State is our ultimate goal."

In a media interaction, the Chief Minister appealed to the Naxalites to shun violence and join the mainstream and reiterated Union Home Minister Amit Shah's assertion that Naxalism would be eliminated from the State by March 2026.

The Opposition Congress in the State also congratulated the forces, with its spokesperson Sushil Anand Shukla claiming that the confidence building measures taken by the previous Congress government in the State had allowed the forces to set up their camps and gain a foothold in Naxal areas. He also said there should not be any questions raised about the encounter by villagers as has been the case in the past incidents.

In a late-night release, the police said there was the possibility of recovery of three to four more bodies.

भारत में नक्सलवाद

- नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से लिया गया है।
- इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई थी, जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पिटाई की थी। विद्रोह की शुरुआत 1967 में हुई थी, जिसका उद्देश्य कानू सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में काम करने वाले किसानों को भूमि का उचित वितरण करना था।
- पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन पूर्वी भारत में फैल गया है; छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में।
- ऐसा माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं।

- माओवाद माओ त्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्जा करने का सिद्धांत है।

कारण

- **आदिवासी असंतोष:**
  - o वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 आदिवासियों को, जो अपने जीवन यापन के लिए वन उपज पर निर्भर हैं, छाल काटने से भी वंचित करता है।
  - o विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों से नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन।

- माओवादियों के लिए आसान लक्ष्य: ऐसे लोग जिनके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं है, उन्हें माओवादी नक्सलवाद में ले जाते हैं।
  - माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला-बारूद और धन मुहैया कराते हैं।
- देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अंतर।
  - सरकार अपनी सफलता को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर मापती है।
  - नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी खुफिया जानकारी का अभाव।
  - उदाहरण के लिए, कुछ गांवों में बुनियादी ढांचे की समस्याएँ अभी भी किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक से जुड़ी नहीं हैं।
- प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं: यह देखा गया है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद भी, प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है।
- नक्सलवाद को सामाजिक मुद्दे के रूप में या सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने को लेकर असमंजस।
- राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मानती हैं और इसलिए इससे लड़ने के लिए कोई पहल नहीं कर रही हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे 2010 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी।
  - o वर्ष 2010 में नक्सलवाद से प्रभावित 223 जिलों की संख्या नौ वर्षों में घटकर 90 रह गई है।
  - o सरकार ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए 'राहत और पुनर्वास नीति' भी शुरू की है।
  - o कम्युनिस्ट पार्टियों के पोलित ब्यूरो की केंद्रीय समिति के सदस्य या तो मारे गए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं।

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: 2018 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।
  - o सरकार के निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक हमलों की आवृत्ति कम हुई है।

UPSC Mains PYQ : 2020

प्रश्न: भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

Page 01 : GS 2 : International relations

लगभग एक दशक में पहली बार विदेश मंत्री एस. जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे।

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, "श्री जयशंकर की यात्रा मुख्य रूप से एससीओ समूह की बैठक के लिए थी, क्योंकि भारत का ध्यान "क्षेत्रीय सहयोग तंत्र" पर है। अब तक किसी भी द्विपक्षीय बैठक का निर्णय नहीं लिया गया है।
- पिछले महीने पाकिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ बैठक का निमंत्रण भेजा था।

शंघाई सहयोग संगठन

- एससीओ की सदस्यता में 2001 से विस्तार हुआ है और वर्तमान में इसके आठ सदस्य देश हैं।
- 1996: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा 'शंघाई फाइव' की स्थापना की गई।
- 2001: 2001 में उज्बेकिस्तान को जोड़ने के बाद, शंघाई फाइव का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया।
- 2015: रूस के उफा में, एससीओ ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया।
- 2016: भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई।
- 2017: अस्ताना में, भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए।
- 2021: यह घोषणा की गई कि ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बन जाएगा।

सदस्य	चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान
पर्यवेक्षक	अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया
संवाद भागीदार	आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की, मिस्र, नेपाल, कतर और सऊदी अरब

महत्व

- सहयोग के क्षेत्र: एससीओ ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है।
- बड़ी आबादी और विश्व जीडीपी को समायोजित करना: यह वैश्विक आबादी का 40%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% और दुनिया के भूभाग का 22% कवर करता है।

Jaishankar will travel to Pakistan for SCO meeting

Suhasini Haidar
NEW DELHI

In the first such visit in nearly a decade, External Affairs Minister S. Jaishankar will travel to Islamabad to attend the Heads of Government meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) on October 15 and 16, the Centre announced on Friday.

The Ministry of External Affairs said Mr. Jaishankar's visit was "mainly" for the SCO grouping's meeting, given India's focus on "regional cooperation mechanisms". No bilateral meetings on the sidelines have been decided thus far, it added.

The last time an Indian External Affairs Minister travelled to Pakistan was Sushma Swaraj in 2015 for the Heart of Asia conference and bilateral talks.

"Mr. Jaishankar will be leading India's delegation to the SCO meeting," MEA spokesperson Randhir Jaiswal told presspersons at a briefing. "As and when the programme develops, the visit develops, we will keep you informed," he said, when asked if there was any request from Pakistan for a bilateral meeting with its Foreign Minister Ishaq Dar.

According to sources, it is also unclear whether Mr. Jaishankar will stay in Islamabad overnight, as he may return to New Delhi the same day.

Mr. Jaishankar may arrive for the formal SCO meeting on October 16 and return to New Delhi the same day.

Officials said the External Affairs Minister's visit was based on "reciprocity", given that despite bilateral tensions, Pakistan had sent its then-Foreign Minister Bilawal Bhutto to attend the SCO Foreign Ministers' meeting in Goa in May 2023.

It is also significant that the Narendra Modi-led government is sending a Minister for an SCO conference, but has refused to attend the SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) summit, due to be held in Pakistan since 2016.

Responding to a question about the recent meeting between the new Bangladesh leader Muhammad Yunus and Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif, where Mr. Yunus called for a "revival" of the eight-nation SAARC process, the spokesperson alleged that it was Pakistan that was "stalling SAARC", not India.

"One particular country has a particular way of doing things, which is stalling SAARC," said Mr. Jaiswal, referring to Pakistan's refusal to move forward on India's suggestions for a Motor Vehicle Agreement (MVA) and South Asian electricity grid initiatives.

The invitation to the SCO meeting was sent to Prime Minister Narendra Modi by the Pakistan government last month.

S. Jaishankar

Minister pledges help to Sri Lanka

COLOMBO

External Affairs Minister S. Jaishankar on Friday met Sri Lanka's new President Anura Kumara Dissanayake, and pledged India's "full support" to the nation's economic recovery. » PAGE 4

- रणनीतिक महत्व: एससीओ में एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को प्राप्त करने और सीमाओं के पार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, एससीओ के प्रयास अपने पूरे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं।
- आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ़ सुरक्षा: इसने न केवल आतंकवाद के खिलाफ़ बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी, सैन्य सहयोग और आर्थिक सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
- QUAD के साथ तुलना: SCO ने अपनी पहलों की श्रृंखला जैसे "शांति मिशन" अभ्यासों के माध्यम से साझा सैन्य और सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की बहुत अधिक क्षमता प्रदर्शित की है, जिसमें सुधारित क्वाड अब तक सभी सदस्यों को शामिल करता है।

भारत के लिए एससीओ का महत्व और प्रासंगिकता

- आतंकवाद-विरोधी: एससीओ आतंकवाद-विरोधी और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष और क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
- क्षेत्रीय स्थिरता: एससीओ के सदस्य के रूप में, भारत के पास मध्य एशिया और उससे आगे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के रखरखाव में योगदान करने का अवसर है।
- संपर्क: एससीओ ने संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है, जो भारत की अपने पड़ोसियों के साथ संपर्क बढ़ाने और अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
- आर्थिक सहयोग: एससीओ भारत को सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे संभावित रूप से बाजारों, प्रौद्योगिकी और निवेश के अवसरों तक अधिक पहुंच हो सकती है।
- बहुपक्षीय कूटनीति: एससीओ भारत को बहुपक्षीय कूटनीति में शामिल होने और सदस्य देशों के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- मध्य एशिया के साथ संबंधों को बढ़ावा देना: एससीओ भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक संभावित मंच है।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

UPSC Prelims PYQ : 2022

प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार करें:

1. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
2. मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था
3. शंघाई सहयोग संगठन

भारत उपरोक्त में से किसका सदस्य है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कोलंबो में श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और द्वीपीय राष्ट्र के आर्थिक सुधार और विकास के लिए भारत के "पूर्ण समर्थन" का वादा किया।

Jaishankar meets Dissanayake, pledges India's support for economic recovery

The External Affairs Minister is the 'first high-level foreign dignitary' to visit Sri Lanka after the leftist leader assumed office; the leaders discuss key issues such as India's security interests, fisheries conflicts, and the political settlement of Sri Lankan Tamils; they extend invitations for bilateral visits

Meera Srinivasan
COLOMBO

External Affairs Minister S. Jaishankar on Friday met Sri Lanka's newly elected President Anura Kumara Dissanayake in Colombo and pledged India's "full support" to the island nation's economic recovery and growth. His discussions with the Sri Lankan leadership covered India's security interests, the persisting fisheries conflict, and the pending political settlement of Sri Lanka's Tamils, according to official statements issued by both sides.

Mr. Jaishankar, on behalf of Prime Minister Narendra Modi, extended an invitation to Mr. Dissanayake to visit India at a mutually convenient date. Mr. Dissanayake, too, extended an invitation to Mr. Modi to visit Sri Lanka, the President's office said.

The visit assumes significance, coming barely a fortnight after Sri Lankans elected leftist leader Mr. Dissanayake as their new President, the first to be held after the country's 2022 economic crisis. Sri Lanka's Ministry of Foreign Affairs said Mr. Jaishankar was the "first high-level foreign dignitary" to visit Sri Lanka after Mr. Dissanayake assumed office.

Sri Lankan president Anura Kumara Dissanayake and External Affairs Minister S. Jaishankar during their meeting on Friday. AP

'Full support'

"Dr. Jaishankar reaffirmed India's full support for Sri Lanka's economic rehabilitation, highlighting India's commitment to assisting in tourism, investment, electricity, energy services, and the dairy industry. He emphasised that Sri Lanka could leverage India's vast market to boost its economic recovery," the presidential media division said following the meeting, adding that Mr. Dissanayake expressed his appreciation for India's support – totalling nearly $4 billion – when the island nation faced a crushing financial meltdown two years ago.

Mr. Jaishankar highlighted ongoing India-backed initiatives in the field of energy production and transmission, fuel and LNG supply, solar electrification of religious places, connectivity, digital public infrastructure, health and dairy development. He highlighted that they would contribute to economic sustainability and provide new streams of revenue, the External Affairs Ministry said in a statement.

The readouts from both sides did not mention the controversial Adani power project in Sri Lanka's Northern Province, which is currently mired in a court battle following stiff opposition from locals and environmentalists. Mr. Dissanayake had in the past questioned its approval, outside of a tender process, and the former government's power purchasing agreement with the company, which he contended was not in Sri Lanka's favour. However, New Delhi's statement following Friday's meeting said Mr. Dissanayake referred to the "potential of export of renewable energy to India, which could help reduce production costs in Sri Lanka and create additional resources".

Collaboration in the island's vital tourism sector was discussed, with Mr. Jaishankar offering to expand the flow of Indian tourists.

Mr. Jaishankar discussed matters of India's security interest in the region. Across meetings, the Sri Lankan leadership assured the top Indian official that they were mindful of India's security concerns and would not allow their territory to be used in a manner inimical to India's security interests, the statements indicated.

Mr. Jaishankar reiterated India's support for "the aspirations of all communities, including Tamils, for equality, justice, dignity, peace while maintaining the unity, territorial integrity and sovereignty of Sri Lanka".

The full and effective implementation of the 13th Amendment of its Constitution and the early conduct of Provincial Council elections will facilitate these objectives, the statement said.

Mr. Dissanayake who, according to this office discussed "areas of mutual interest, including fisheries and promoting national unity" with Mr. Jaishankar, promised in his poll manifesto to deliver a political settlement to the Tamils through a new Constitution. His government has said efforts would begin after the parliamentary elections.

Release of fishermen

Mr. Jaishankar also raised concerns pertaining to Indian fishermen who are detained in Sri Lanka. "He pressed for their early release, as well as of their boats, and reconsideration of the heavy fines imposed on them," the Indian statement said.

For many years, war-affected Sri Lankan Tamil fishermen have been urging fishermen in Tamil Nadu to refrain from using the bottom-trawling fishing method that is known to severely deplete the marine ecosystem. However, the Indian fishermen, from Tamil Nadu's coastal districts, are frequently arrested by Sri Lanka for fishing illegally in the country's territorial waters, that too using the destructive fishing method. A total of 50 Indian fishermen from Mayiladuthurai, Pudukkottai, and Nagapattinam were released on Friday. They would be repatriated from Sri Lanka to Tamil Nadu later this week, the Indian High Commission said.

- दोनों पक्षों द्वारा जारी आधिकारिक बयानों के अनुसार, श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ उनकी चर्चा में भारत के सुरक्षा हितों, मत्स्य पालन संघर्ष और श्रीलंका के तमिलों के लंबित राजनीतिक समाधान पर चर्चा हुई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से श्री जयशंकर ने श्री दिसानायके को पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भारत आने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि श्री दिसानायके ने भी श्री मोदी को श्रीलंका आने का निमंत्रण दिया।

- यह यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीलंका द्वारा वामपंथी नेता श्री दिसानायके को अपना नया राष्ट्रपति चुने जाने के बमुश्किल दो सप्ताह बाद यह यात्रा हो रही है, जो देश के 2022 के आर्थिक संकट के बाद पहली यात्रा है।
- श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जयशंकर श्री दिसानायके के पदभार ग्रहण करने के बाद श्रीलंका आने वाले "पहले उच्च-स्तरीय विदेशी गणमान्य" थे।

भारत और श्रीलंका के बीच संबंध

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - o भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है।
  - o दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं, कई श्रीलंकाई अपनी विरासत भारत से जोड़ते हैं। भारत में उत्पन्न बौद्ध धर्म भी श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण धर्म है।

भारत से वित्तीय सहायता:

- o भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जो देश के लिए संकट से उबरने के लिए महत्वपूर्ण थी।
- o विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण श्रीलंका 2022 में एक भयावह वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जो 1948 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब है।

ऋण पुनर्गठन में भूमिका:

- o भारत ने श्रीलंका को अपने ऋण पुनर्गठन में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और लेनदारों के साथ सहयोग करने में भूमिका निभाई है।
- o भारत श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के लिए अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला पहला देश बन गया।

कनेक्टिविटी के लिए संयुक्त विजन:

- o दोनों देश एक संयुक्त विजन पर सहमत हुए हैं जो लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह कनेक्टिविटी और बिजली व्यापार के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी सहित व्यापक कनेक्टिविटी पर जोर देता है।

आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ईटीसीए):

- o दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए ईटीसीए की संभावना तलाश रहे हैं।

- **बहु-परियोजना पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता:**
  - o भारत और श्रीलंका दोनों भारत के दक्षिणी भाग से श्रीलंका तक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
  - o इस पाइपलाइन का उद्देश्य श्रीलंका को ऊर्जा संसाधनों की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास और प्रगति में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

- **भारत के यूपीआई को अपनाना:**
  - o श्रीलंका ने अब भारत की यूपीआई सेवा को अपना लिया है, जो दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  - o व्यापार निपटान के लिए रुपये का उपयोग श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और मदद कर रहा है। ये श्रीलंका की आर्थिक सुधार और विकास में मदद करने के लिए ठोस कदम हैं।

- **आर्थिक संबंध:**
  - o अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के 60% से अधिक निर्यात को भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ मिलता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक भी है।
  - o वर्ष 2005 से 2019 के बीच भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

- **रक्षा:**
  - o भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य (मित्र शक्ति) और नौसेना अभ्यास (एसएलआईएनईएक्स) करते हैं।

- **समूहों में भागीदारी:**
  - o श्रीलंका बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) और सार्क जैसे समूहों का भी सदस्य है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है।

- **पर्यटन:**
  - o वर्ष 2022 में, भारत 100,000 से अधिक पर्यटकों के साथ श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत था।

भारत और श्रीलंका संबंधों का महत्व

- **क्षेत्रीय विकास पर ध्यान:**
  - o भारत की प्रगति उसके पड़ोसी देशों के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है, और श्रीलंका का लक्ष्य दक्षिण एशिया में दक्षिणी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करके अपने विकास को बढ़ाना है।

- **भौगोलिक स्थिति:**
  - o पाक जलडमरूमध्य के पार भारत के दक्षिणी तट के पास स्थित श्रीलंका दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - o हिंद महासागर व्यापार और सैन्य अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, और प्रमुख शिपिंग लेन के चौराहे पर श्रीलंका का स्थान इसे भारत के लिए नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है।
- **व्यापार और पर्यटन में आसानी:**
  - o दोनों देशों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों के बढ़ने से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक लेन-देन सरल होगा।
  - o यह प्रगति न केवल व्यापार को सुव्यवस्थित करेगी बल्कि दोनों देशों के बीच पर्यटन आदान-प्रदान के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगी।

UPSC Mains PYQ : 2022

प्रश्न: 'भारत श्रीलंका का पुराना मित्र है।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका में हाल के संकट में भारत की भूमिका पर चर्चा करें।

Page 09 : GS 1 : Indian Society

आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह चेंचू को पारंपरिक आजीविका पर निर्भरता और सरकारी रोज़गार योजनाओं में बदलाव के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- उनका संघर्ष उनके जीवन की स्थितियों और आर्थिक एकीकरण में सुधार के लिए अनुरूप हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

Forgotten in the forest: An elderly man, belonging to the Chenchu tribe, posing with his bow and arrow, in Panukumadugu gudem in Dornala mandal of Prakasam district. Traditionally a hunter-gatherer tribe, the Chenchus now rely on subsistence farming for a living.

A tribe out of time

The Chenchus of Panukumadugu have lived in the dense Nallamala forests for centuries, their existence intertwined with the wilderness around them. However, their inability to keep up with the relentless pace of modernisation has led to dwindling work opportunities under the MGNREGS. **Nellore Sravani** writes how the Chenchus, caught between an ancestral past and an uncertain future, are grappling with isolation, poverty, and an erosion of their traditional way of life

Sitting under a tree on a cot woven from leaves and logs, Dasari Kotaiah sighs wearily when asked about what he's going to have for lunch.

"The usual," he replies. A thin meal of rice and *pachhadi* – a simple chutney made from chilli, tamarind, and onion – has remained the family's staple diet for years now. "This is our food for 25 days in a month. We cannot afford anything beyond that. Where is the money?" Kotaiah asks, shaking his head at the thought of buying fruits or vegetables from the market. His wry laugh speaks of a life where even the simplest comforts are out of reach.

Kotaiah lives in a hamlet called Panukumadugu in Dornala mandal of Prakasam district. The hamlet is home to the Chenchus, said to be the oldest aboriginal, Telugu-speaking tribe and the most vulnerable of the 12 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in undivided Andhra Pradesh.

Around 25 kilometres away is Dornala, a small town at the edge of the Nallamala forest in Prakasam district. A pitstop for Srisailam-bound devotees, Dornala has had a growth spurt in the past two decades with hotels and eateries coming up. Dornala is the nearest go-to place for the Chenchu villages, including Panukumadugu. The contrast between the town and the hamlet of Panukumadugu is stark, more than what meets the eye.

Most of the dwellings in Panukumadugu are single-room thatched huts, simple and sparse, with conical or square roofs and rounded bases. Of the few pucca houses built under the Indiramma Illu housing scheme, many are in disrepair. The only sturdy structure in this hamlet is the Anganwadi, where a single female teacher educates around 30 children.

While Dornala thrives with an expanding menu of cuisines in its restaurants, life for the Chenchus seems to be moving in the opposite direction, with development passing them by.

"Ever since we stopped working under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in 2022, life has become much harder," Kotaiah explains. "The wages I earn as an agricultural labourer aren't enough to support a family of 22," says Kotaiah, who doesn't remember his exact age, though his Aadhaar card lists him as 59. Both he and his wife take whatever work they can find, earning ₹250 each per day.

But it's still not enough. "We need the 'karuvu pani' (MGNREGS) to be brought back," he says, a statement that is being echoed by other younger men and women of the village.

> A reason behind the disillusionment among Chenchus with the new system of MGNREGS could be the insistence on first getting Aadhaar, and then linking it to one's bank account and job card. With most Chenchus being non-literate, they were probably too intimidated by all the red tape
>
> CHAKRADHAR BUDDHA
> Social researcher

Left behind

However, the issue is quite complex. The Chenchus, who have steadfastly held on to their way of life, possess only a rudimentary understanding of modern society and find it difficult to adapt to the world that exists outside their village. "Most Chenchus lack post-industrialisation skills. They are still living in a pre-agrarian setup. To catch up with modern society, they first need to learn agricultural skills, and then must come to terms with industrialisation," explains Chakradhar Buddha, a senior researcher with LibTech India, a consortium of activists and academics that has extensively studied the impact that MGNREGA has had on the tribe for years.

Chenchus are characterised by extremely low literacy rates, a subsistence economy, and a stagnant or declining population. The total Chenchu population in Andhra Pradesh stands at 28,349.

"The Chenchus are heavily dependent on the forest for food and other necessities. This deep reliance has made it difficult for them to migrate to other areas and has isolated them from the outside world. As many live deep within the forest, numerous development programmes, including MGNREGS, have struggled to reach them," says Mr. Chakradhar.

In response, the A.P. government launched the MGNREGS Chenchu Special Project in 2009, aimed at alleviating poverty and improving their socioeconomic conditions. Locally, the Chenchus refer to it as '15 rojula pani, upaadhi haami' (15 days of guaranteed work) or 'ITDA pani' (ITDA work).

The project was carefully tailored to the specific needs of the Chenchus, taking into account their physical strength, food insecurities, accessibility challenges, lifestyle, and cultural practices. Managed by the Integrated Tribal Development Agencies (ITDAs), the special initiative provided 180 days of employment per individual, compared to the standard 100 days per household in other areas. Chenchus were able to work 15 days each month, year round, on individual or community land.

Ill-thought-out moves

However, in December 2021, the Union government decided to bring all State-specific Management Information Systems (MIS), the operating software for MGNREGA, under the Centrally-controlled MIS, which standardised MGNREGS operations nationwide.

"This aligned the Chenchu Special Project with the broader national framework, which meant that policies in place for a person outside applied to Chenchus as well. This move of the government has had a devastating impact on the Chenchus, because of the reduction of employment days for them, removal of work concession and shift to bank-based payments," explains Mr. Chakradhar.

"A reason behind the disillusionment among the Chenchus with the new system of MGNREGS could be the insistence on first obtaining Aadhaar and then linking it to one's bank account and job card for disbursal of wages. With most Chenchus being non-literate, they were probably too intimidated by all the red tape," Mr. Chakradhar says, adding that the Chenchu Special Project was precisely aimed at helping the Chenchus overcome such hurdles.

"Earlier, Chenchus in 125 *gudems* (villages) across the three districts were going for MGNREGS work. But now, no one is interested in coming. We are also demanding that the special project be revived," said the ITDA Srisailam Project Officer.

As per a Socio-Economic Survey taken up by the A.P. government in 2020-21, the project generated 69 lakh person days of employment between 2009 and 2021.

But now, most of the people in Panukumadugu, Marripalem and Billagundipenta 'gudems' in Prakasam district have stopped going for MGNREGS work. As per the data collected by LibTech India, only about 1,500 of the 4,000 enrolled households are taking up work across Atmakur, Dornala, and Yerragondapalem mandals.

A major deterrent for the villagers is the uncertainty surrounding the wage disbursement process. Kotaiah, like most others here, cannot read or write. At Panukumadugu, most of the 75 families do not have a mobile phone or a two-wheeler and more than 70 people, including children, do not have Aadhaar cards. Without Aadhaar, they are excluded from the Public Distribution System (PDS) as well as the Aarogyasri health insurance scheme.

Starting from January 1, 2024, the Aadhaar-based payment system (ABPS) was made mandatory for payment of wages to workers under MGNREGS. Now, the national framework requires a job-seeker to get their job card seeded with their Aadhaar card and then link their Aadhaar card with their bank account. This has become an overwhelmingly daunting task for the Chenchus.

> Now, we don't even know if wages are being deposited into our accounts. No one explains what's happening. Those who have bank accounts fear being cheated since they cannot read or write. Bankers often get irritated when we keep asking
>
> BHUMANI VENKATESAM
> Chenchu elder

"Earlier, most of us would work under the scheme because cash was handed out to us every month. Now, we don't even know if wages are being deposited into our accounts. No one explains what's happening. Those who have bank accounts fear being cheated since they cannot read or write. Bankers often get irritated when we keep asking," Kotaiah says.

Except for one or two people, no one in this habitation has a mobile phone. The only way they can find out if money has been deposited is to visit a bank in Dornala, which is 25-30 km away, at least three times a month.

While Panukumadugu is located in the plains, many Chenchu gudems are situated within the Nagarjuna-Srisailam Tiger Reserve (NSTR) and are deep in the forest, making trips to Dornala expensive.

Bhumani Venkatamma, a Chenchu from Marripalem, located deep in the forest, shares that the Chenchus struggle to find work for most of the year.

"At best, we get work for six months when farmers hire us for the chilli or cotton fields. Sometimes they ask us to herd cattle, which pays us about ₹200-₹300 per day. But we don't do that every day; it's only twice a week," she says, adding that in October, November, and December, they have nothing to do.

Haves, and have-nots

Ironically, the Aadhaar card has become a subtle source of discord between those who have it and those who don't.

"Only those with Aadhaar are eligible for receiving wages under the new system. Not just that, but other things like coverage under Aarogyasri, school admission and getting ration cards are all possible only if one has Aadhaar," Venkatamma says, adding that some people do not have Aadhaar yet.

When asked why some people do not have Aadhaar cards, activists said many do not have birth certificates. The whole process of getting a birth certificate itself is quite tedious, it is learnt.

"Even so, we are not comfortable with our payments being deposited into bank accounts. There are many people in our tribe with the same name. Apart from me, there are two other women named Bhumani Venkatamma. Once, a villager's payment was wrongly credited into the account of another person with the same name. Ever since then, we have been wary of the whole thing," Venkatamma shares.

Traditionally, the Chenchus have been foragers. In *The Chenchus of Andhra Pradesh*, anthropologist Md. Azeez Mohidden notes that they rely on the forest economy, gathering leafy vegetables, wild fruits, tubers, and roots for consumption, while earning income from selling Non-Timber Forest Produce (NTFP) like gum, honey, soapnuts, and beed at the Girijan Cooperative Corporation (GCC). However, LibTech India activists report that restrictions on their movement in the forest and the collection of forest produce have increased recently due to wildlife conservation laws.

"We sell our produce at the GCC, but the returns are insufficient. We also sell along the Srisailam ghat road or at the Devasthanam," says Venkatamma, who struggles to feed her family of six, including four children. While she has a ration card allowing her to receive 35 kg of PDS rice per month, she finds it inadequate.

P. Srinivasa Rao, former Deputy District Medical and Health Officer of ITDA-Srisailam, recalls: "About 25 years ago, when we visited the gudems for work, we were fed various curries made from leafy vegetables found in the forest. As many as 23 types of leaves were used in cooking. Each night, a family member would venture into the forest with bows to hunt small animals like rabbits and peacocks for the next day's meal. These days, we neither find these animals in the forest nor do the Chenchus utilise leaves as they once did.

This situation has led to a higher incidence of nutritional deficiencies among children. "Child marriages and consanguineous marriages are common in the community. These factors have made them more susceptible to sickle cell anemia and thalassemia, with high infant and maternal mortality rates," says Dr. Srinivasa Rao.

Venkatamma recalls how they used to spend money on milk and lentils before the project was halted. She even managed to save enough to buy a TV and some gold, she smiles. Unfortunately, her brother broke the TV in a drunken fit, and now she has no money to repair it.

"We are called the protectors of the forest, yet ironically, we are being excluded from it in the name of tiger conservation," laments Bhumani Venkatesam, another elder from Billagundipenta, a village deep in the forest. He notes that while the elders at least had access to forest produce, the youth are left with neither the forest nor any means of earning a livelihood.

The Chenchus received pattas under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, commonly known as the Forest Rights Act (FRA). During their time in MGNREGS work, those who had received pattas were tasked with clearing land, creating trenches, and removing pebbles.

The project aimed to transform the tribe from hunter gatherers to producers. Under the special project, many Chenchus worked on their own land and received government funds for purchasing pesticides and seeds. However, with its discontinuation, they are unsure how to manage their land.

Meanwhile, with dilapidated houses, irregular incomes, limited transportation, and a lack of electricity in some gudems, the Chenchus stare at an uncertain future.

चेंचू जनजाति

- चेंचू भारत की सबसे पुरानी आदिवासी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- परंपरागत रूप से, चेंचू भोजन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों के लिए जंगल पर निर्भर रहने वाले वनवासी हैं।
- इस जनजाति की साक्षरता दर बेहद कम है और इसे सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- आंध्र प्रदेश में चेंचू की आबादी लगभग 28,349 है।
- उनके पास आधुनिक समाज की बुनियादी समझ है, जिससे अनुकूलन मुश्किल हो जाता है।
- यह जनजाति जंगल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो ऐतिहासिक रूप से उनकी आजीविका और भरण-पोषण का स्रोत रहा है।

चेंचू जनजाति के सामने आने वाली समस्याएँ

- आर्थिक कमज़ोरी: परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए अपर्याप्त आय के साथ कम वेतन वाले कृषि श्रम पर निर्भरता।
- रोज़गार का नुकसान: MGNREGS चेंचू विशेष परियोजना को बंद करने से काम के अवसर कम हो गए और आय असुरक्षा हो गई।
- आधार से जुड़ी चुनौतियाँ: वेतन भुगतान के लिए अनिवार्य आधार पंजीकरण कम साक्षरता और प्रौद्योगिकी तक पहुँच की कमी के कारण बाधाएँ पैदा करता है।
- स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: पोषण संबंधी कमियाँ, उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर, और आनुवंशिक विकारों का प्रचलन।
- वन पहुँच प्रतिबंध: संरक्षण कानून वन संसाधनों तक उनकी पहुँच को सीमित करते हैं, जिससे उनकी पारंपरिक आजीविका पद्धतियाँ प्रभावित होती हैं।
- आवास और अवसंरचना: अपर्याप्त आवास, बिजली की कमी और खराब परिवहन सुविधाओं के साथ बिगड़ती जीवन-स्थितियाँ।
- सांस्कृतिक विस्थापन: पारंपरिक शिकारी-संग्राहक जीवनशैली से आधुनिक कृषि पद्धतियों में संक्रमण में कठिनाई।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)

- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) भारत में हाशिए पर पड़े जनजातीय समुदाय हैं, जिनकी विशेषता निम्न विकास संकेतक, कृषि-पूर्व आजीविका और घटती आबादी है। सरकार द्वारा पहचाने गए 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 PVTG हैं।
- उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना तक सीमित पहुँच जैसी गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम, जैसे कि पीवीटीजी विकास योजना, का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से इन समुदायों का उत्थान करना है।

UPSC Prelims PYQ : 2013

प्रश्न: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकारी कौन होगा?

(क) राज्य वन विभाग
(ख) जिला कलेक्टर/उपायुक्त
(ग) तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी/मंडल राजस्व अधिकारी
(घ) ग्राम सभा

उत्तर: (घ)

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

Report In News : EnviStats India 2024

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने "एनविस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण लेखा" प्रकाशन का लगातार 7वां अंक संकलित और जारी किया।

एनवीस्टेट्स इंडिया 2024 के बारे में:

- इसे पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEAA) के अनुसार संकलित किया गया है।
- वर्तमान प्रकाशन जो श्रृंखला में सातवाँ है, ऊर्जा खातों, महासागर खातों, मृदा पोषक तत्व सूचकांक और जैव विविधता को कवर करता है।

एनवीस्टेट्स इंडिया 2024 की मुख्य विशेषताएँ

- 2000 से 2023 की अवधि के दौरान कुल संरक्षित क्षेत्र के लिए संख्या में लगभग 72% और क्षेत्र में लगभग 16% की वृद्धि हुई है।
- मैंग्रोव का कवरेज, जो महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण उप-पारिस्थितिकी तंत्र है, 2013 से 2021 के वर्षों में लगभग 8% बढ़ा है।
- रिपोर्ट में भारत की टैक्सोनॉमिक फ़ॉनल और फ्लोरल विविधता, तेंदुए और हिम तेंदुए की स्थिति और हितधारक मंत्रालयों/एजेंसियों के डेटा का उपयोग करके आनुवंशिक संरक्षण पर जानकारी भी शामिल है।
- इसके अलावा, टैक्सोनोमिक समूहों द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची की प्रजाति समृद्धि को IUCN से स्थानिक डेटासेट का उपयोग करके संकलित किया गया है।

पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन की प्रणाली क्या है?

- यह अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच बातचीत का वर्णन करने के लिए एक सहमत अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है, साथ ही साथ पर्यावरणीय परिसंपत्तियों के स्टॉक और स्टॉक में परिवर्तन भी है।
- इसका उद्देश्य अन्य विषयों के दृष्टिकोणों को एकीकृत करना है और, जहाँ प्रासंगिक हो, पर्यावरणीय आर्थिक खातों के लिए सूचना का एक बेहतर निकाय प्रदान करना है।
- SEEA के दो पक्ष हैं- SEEA-केंद्रीय ढांचा (SEEA-CF) और SEEA-पारिस्थितिकी तंत्र लेखा (SEEA-EA)
  o SEEA-केंद्रीय ढांचा: यह पर्यावरण के व्यक्तिगत घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए सामग्री और स्थान प्रदान करते हैं।
  o SEEA-पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन: यह SEEA-CF का एक पूरक ढांचा है और आवासों और परिदृश्यों के बारे में डेटा को व्यवस्थित करने, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मापने, पारिस्थितिकी तंत्र परिसंपत्तियों में परिवर्तनों पर नज़र रखने और इस जानकारी को आर्थिक और अन्य मानवीय गतिविधि से जोड़ने के लिए एक एकीकृत और व्यापक सांख्यिकीय ढांचा तैयार करता है।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 06 Editorial Analysis

Kerala urgently needs to identify risk zones

Srikumar Chattopadhyay

Scientist (retired), Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram

K. Soman

Scientist (retired), Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram

On July 30, two villages, Mundakkai and Chooralmala, in the Wayanad district of Kerala, were hit by landslides. On October 4, while noting that the disaster ranked among the deadliest in India, Chief Minister Pinarayi Vijayan said that 231 people had died and 41 remained missing. The catastrophic event has once again exposed our helplessness in the face of nature's fury. At the same time, it has raised questions about our approach to disaster management not only in the area of Wayanad that was affected this time and that has suffered a few deadly landslides over the last four decades, but for the State as a whole.

No longer relatively disaster-free

With the sea to its west and the Western Ghats to its east, Kerala used to be considered a relatively disaster-free zone. Its development activities have taken place on this premise. Settlements are distributed throughout the State, from the coastline to the steep hill slopes. Kerala is perhaps the only State where human settlements have sprung up along the coastal line. Though the forest boundary is frozen, there are encroachments by the people and for development projects. Along with settlements, roads and other infrastructure have been built with complete disregard for natural drainage and slope stability. The average population density of the parts of the Western Ghats in Kerala is well above the all-India average.

The natural advantage of being relatively disaster-free seems to be waning. In the last few decades, the intensity and frequency of disasters have increased. Kerala has three distinct geographic zones, and all three are facing disasters, especially floods and landslides. Coastal erosion, a regular phenomenon, has affected more than 250 kilometres of the total coastal length of 590 km in the State. Besides, sea surge has affected different parts of the coast. The lowlands and midlands suffer from floods. Parts of the lowlands surrounding the Vembanad lake get inundated during every monsoon. The World Meteorological Organization described the Kerala floods of 2018 as the 'floods of the century' and attributed the disaster to climate change. Landslides in the Western Ghats are also becoming regular during every monsoon.

> Once landslide susceptibility maps surrounding population centres are ready, monitoring the triggering mechanism would ensure that timely warnings are provided

Landslide inventory map needed

Wayanad, located to the east of the Western Ghats bordering the Mysore plateau, is characterised by deep gorges and ravines. Like the river Sharavati, the Chaliyar also originates in the eastern side of the Western Ghats. Both these rivers cut across the mountain range and debouch into the Arabian Sea, in spite of the easterly tilt of the Wayanad-Mysore plateaus. This can be attributed to the existence of tectonic factors. A spatial correlation exists between tremors and landslides. Incidences of fractures/cracks have been reported from Wayanad and Idukki post landslides. Tremors were felt in parts of Wayanad after the July landslide as well. Recurring incidences of landslides and the huge human and economic losses call for scientific re-appraisal of the causative factors, which are now being simplified and confined to parameters such as slope, soil thickness, rainfall intensity and duration, and land use change. The ongoing debates show that there is a gap in understanding the incidence of landslides in this region.

Global research in this field calls for a nuanced approach. We need a landslide inventory map of each region/area. To finalise zones susceptible to landslides, we can prepare a landslide susceptibility map factoring in the geological set up (lithology, structure and tectonics, rock composition, physico-mechanical properties), slope, soil characteristics, hydrologic parameters, drainage and infiltration, vegetation cover, human activities such as mining and quarrying, slope alteration, and agricultural activities. Once such maps surrounding population centres are ready, monitoring the triggering mechanism (rainfall or tremors in the case of Kerala) would ensure that timely warnings of landslides are provided, and lives saved. The State and trained local self-help groups can do this together.

Due to rapid warming of the Arabian Sea, there is an increased risk of extreme weather and climate events, such as floods, heat waves, and cyclones. The heat content of the Indian Ocean has risen rapidly since the 2000s. There has been an anomalous increase of 1.2°C in summer sea surface temperatures over the last 100 years in the generally cool western Indian Ocean (Arabian Sea). This has created an environment conducive for cyclogenesis (development or strengthening of cyclonic circulation in the atmosphere) in the Arabian Sea. The impact of these changes is being felt on Kerala. In 2017, Cyclone Ockhi hit the State. It was the most severe cyclonic storm to affect Kerala in recent memory.

On the whole, the 'safe operating space', a term coined by Johan Rockstrom and the group at the Stockholm Resilience Centre in the case of global environmental change, is shrinking in Kerala. The occurrence of staggered events of floods and landslides, and simultaneous landslides on either side of the hill ranges, as in Wayanad and Vilangad (Kozhikode district) this time, and at Puthumala (Wayanad district) and Kavalappara (Malappuram district) in 2019, also warrant elucidation.

A paradigm shift

Under these circumstances, there is a need for a paradigm shift in disaster management practices, which are mostly reactive, top-down, and revolve around rescue, relief, and rehabilitation. Globally, this has given way to a more proactive and comprehensive approach of addressing all aspects of a disaster cycle, such as preparedness, resilience, risk reduction, mitigation, reconstruction, recovery, response, and relief. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction provides guidelines for disaster risk reduction. It recognises the primary role of the State in disaster risk reduction but says that the State should share this responsibility with other stakeholders including local governments, the private sector, and communities. We need to understand the risk of disaster, strengthen disaster risk governance to manage the risk of disaster; invest in disaster risk reduction for resilience; and enhance disaster preparedness for effective response to 'build back better'.

First, Kerala needs to work out disaster risk zones based on multiple criteria covering both physical and social components within a social ecological frame with the help of subject experts and generate a permanent database. As landslides and floods follow watershed boundaries, the disaster risk zones must be translated according to the watersheds/river basins. Second, Kerala needs the people's participation in preparing disaster risk maps. Given its experience in the People's Plan Campaign, it is important for Kerala to introduce a community-based disaster risk management in which at-risk communities are actively engaged in identifying, analysing, planning, implementing, monitoring, and evaluating disaster risk reduction initiatives. This would provide opportunities for strengthening communication, discussion, and learning within the community and between the community and the local and Central government. It would also ensure a bottom-up approach, help reduce tension and potential conflicts and pave the way to integrate disaster risk management in local level development. A quadruple helix model involving community and social organisations, academia/research institutes, the government, and business and industry may be useful.

GS Paper 03 : आपदा प्रबंधन

(UPSC CSE (M) GS-3 2021): हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के कारणों में अंतर बताइए। (150 w/10m)

UPSC Mains Practice Question : भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में केरल के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आपदा तैयारी और लचीलेपन को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। (250 w/15m)

संदर्भ :

- लेख में अनियोजित विकास, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के कारण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और बाढ़ के प्रति केरल की बढ़ती संवेदनशीलता पर चर्चा की गई है।
- यह सक्रिय आपदा प्रबंधन और समुदाय-आधारित जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है।

परिचय

- केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन ने राज्य की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है।
- भारत में सबसे घातक घटनाओं में से एक, हाल ही में हुई इस घटना ने केरल में आपदा प्रबंधन दृष्टिकोणों के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है।

केरल में आपदा जोखिम में बदलाव

- केरल, जिसे पहले अपेक्षाकृत आपदा-मुक्त क्षेत्र माना जाता था, में आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि देखी गई है।
- बस्तियाँ तटीय क्षेत्रों से लेकर खड़ी पहाड़ी ढलानों तक फैली हुई हैं, जहाँ प्राकृतिक जल निकासी और ढलान स्थिरता पर विचार किए बिना बुनियादी ढाँचा बनाया गया है।
- केरल के 590 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से 250 किलोमीटर से अधिक तटीय कटाव प्रभावित करता है, जबकि निचले इलाकों में बार-बार बाढ़ आती है।
- पश्चिमी घाटों में भूस्खलन और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि जलवायु परिवर्तन और अरब सागर के तेजी से गर्म होने के कारण होती है।

भूस्खलन सूची मानचित्र की आवश्यकता

- वायनाड, जो गहरी घाटियों और खड्डों से घिरा हुआ है, भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, और ऐसी घटनाओं से पहले अक्सर भूकंप आते हैं।

- भूस्खलन के कारणों का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि समझ अभी भी अधूरी है।
- भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए केरल को भूस्खलन सूची मानचित्र की आवश्यकता है, जिसमें भूविज्ञान, मिट्टी की विशेषताओं और मानवीय गतिविधियों जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।
- इससे बारिश या भूकंप जैसे ट्रिगरिंग तंत्रों की बेहतर निगरानी की सुविधा होगी, जिससे समय पर चेतावनी दी जा सकेगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- अरब सागर के गर्म होने से केरल में बाढ़, लू और चक्रवात जैसी चरम मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
- समुद्र के बढ़ते तापमान ने इस क्षेत्र को चक्रवात के अनुकूल बना दिया है, जो केरल के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है।
- चक्रवात ओखी जैसी घटनाएँ केरल की भेद्यता पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती हैं।

आपदा प्रबंधन में प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता

- केरल की आपदा प्रबंधन प्रथाएँ प्रतिक्रियात्मक हैं, जो बचाव, राहत और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा सुझाए गए अनुसार, सक्रिय प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता है।
- केरल को जलग्रहण क्षेत्रों/नदी घाटियों को कवर करते हुए कई भौतिक और सामाजिक मानदंडों के आधार पर आपदा जोखिम क्षेत्रों को परिभाषित करना चाहिए।

समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन

- आपदा जोखिम मानचित्र तैयार करने और प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने में लोगों की भागीदारी आवश्यक है।
- केरल में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की शुरूआत समुदाय की भागीदारी को मजबूत कर सकती है और स्थानीय विकास में आपदा जोखिम प्रबंधन को एकीकृत कर सकती है।
- सामुदायिक संगठनों, शिक्षाविदों, सरकार और उद्योग को शामिल करते हुए एक चौगुनी हेलिक्स मॉडल, आपदाओं के प्रति लचीलापन और प्रतिक्रिया को बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- सबसे पहले, केरल को विषय विशेषज्ञों की मदद से सामाजिक पारिस्थितिक ढांचे के भीतर भौतिक और सामाजिक दोनों घटकों को कवर करने वाले कई मानदंडों के आधार पर आपदा जोखिम क्षेत्रों पर काम करने और एक स्थायी डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता है। चूंकि भूस्खलन और बाढ़ जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाओं का अनुसरण करते हैं, इसलिए आपदा जोखिम क्षेत्रों को जलग्रहण क्षेत्रों/नदी घाटियों के अनुसार अनुवादित किया जाना चाहिए।
- दूसरा, केरल को आपदा जोखिम मानचित्र तैयार करने में लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। जन योजना अभियान में अपने अनुभव को देखते हुए, केरल के लिए समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन शुरू करना महत्वपूर्ण है, जिसमें जोखिम वाले समुदाय आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों की पहचान, विश्लेषण, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करने में सक्रिय रूप से शामिल हों।

- इससे समुदाय के भीतर और समुदाय और स्थानीय और केंद्र सरकार के बीच संचार, चर्चा और सीखने को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। यह नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा, तनाव और संभावित संघर्षों को कम करने में मदद करेगा और स्थानीय स्तर के विकास में आपदा जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- समुदाय और सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों/शोध संस्थानों, सरकार और व्यापार और उद्योग को शामिल करने वाला एक चौगुना हेलिक्स मॉडल उपयोगी हो सकता है।

इसरो द्वारा भारत का भूस्खलन एटलस:

- भारत वैश्विक स्तर पर भूस्खलन की आशंका वाले शीर्ष 5 देशों में से एक है।
- अन्य देश चीन, अमेरिका, इटली और स्विटजरलैंड हैं।
- भारत में, लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किमी (भूमि क्षेत्र का 12.6%) भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है।
- भारत में रिपोर्ट किए गए भूस्खलन इस प्रकार वितरित किए जाते हैं:
  - o उत्तर-पश्चिमी हिमालय में 66.5%
  - o पूर्वोत्तर हिमालय में 18.8%
  - o पश्चिमी घाट में 14.7%
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, कई विकासशील देशों में भूस्खलन के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का 1% से 2% तक हो सकता है

भारत में प्रमुख भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (कुल भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का लगभग 50% हिस्सा)
- हिमालय के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर।
- पश्चिमी घाट के साथ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु
- पूर्वी घाट के साथ आंध्र प्रदेश में अराकू क्षेत्र।
- केरल में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में है, भूस्खलन-प्रवण के रूप में मैप किया गया है।

भारत में प्रमुख भूस्खलन

- केदारनाथ, उत्तराखंड 2013 में
- पेटीमुडी, केरल 2020 में
- मुंबई, महाराष्ट्र 2021 में
- तुपल, मणिपुर 2022 में
- रायगढ़, महाराष्ट्र 2023 में
- आइजोल, मिजोरम 2024 में
- शिरुर, कर्नाटक 2024 में

पश्चिमी घाट में भूस्खलन हिमालय क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है?

क्षेत्र	कारण
पश्चिमी घाट	▪ सघन वर्षा ▪ पहाड़ियों पर अत्यधिक भार ▪ खनन और उत्खनन ▪ मानवजनित गतिविधियाँ जैसे कृषि गतिविधियाँ, पवन चक्की परियोजनाएँ, आदि ▪ पतली मिट्टी पर घनी वनस्पति के साथ वन विखंडन
हिमालय	▪ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण उच्च भूकंपीयता ▪ आसानी से अपरदनशील तलछटी चट्टानें ▪ युवा और ऊर्जावान नदियाँ (जैसे: गंगा, यमुना, झेलम आदि) जिनमें उच्च अपरदनशीलता होती है ▪ भारी बारिश और बर्फबारी ▪ वनों की कटाई, झूम खेती, सड़क निर्माण आदि जैसे मानवजनित कारक।

पश्चिमी घाटों पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011 (माधव गाडगिल की अध्यक्षता में):**
  - सभी पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित किया जाए
  - केवल वर्गीकृत क्षेत्रों में सीमित विकास की अनुमति दी जाए।
  - पश्चिमी घाटों को ईएसए 1, 2 और 3 में वर्गीकृत किया जाए, जिसमें ESA-1 को उच्च प्राथमिकता दी जाए, जहां लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियां प्रतिबंधित हों।
  - शासन प्रणाली को ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण (ग्राम सभाओं से) के रूप में निर्दिष्ट किया जाए।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (डब्ल्यूजीईए) का गठन किया जाए, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियां दी जाएं।
  - रिपोर्ट की आलोचना की गई कि यह पर्यावरण के अधिक अनुकूल है और जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती।

- **कस्तूरीरंगन समिति, 2013: इसने गाडगिल रिपोर्ट के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की:**
  - पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ईएसए के अंतर्गत लाया जाना।
  - ईएसए में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  - किसी भी ताप विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और विस्तृत अध्ययन के बाद ही जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - लाल उद्योग यानी जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं, उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
  - बसे हुए क्षेत्रों और बागानों को ईएसए के दायरे से बाहर रखा जाना इसे किसान समर्थक दृष्टिकोण बनाता है।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY